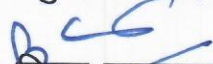


सम्बन्ध में घटना वही की नकल आदि दस्तावेज होना आवश्यक है। इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार पर पश्चावर्ती अतिक्रमण मानकर विधि विरुद्ध अपीलान्त को सजा से दण्डित किया गया है। तो हमारी सुविचारित राय में सिविल जैसे कठोर कारावास की सजा को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। हम वकील अपीलान्त के कथनों से सहमत हैं।

अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार सपोटरा जिला करौली का निर्णय दिनांक 25.6.2018 में से 90 दिवस का सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.1.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति० 
जिला कलक्टर
करौली